



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 05 Dec, 2025

Edition : International | Table of Contents

Page 01 & 04 Syllabus : GS 2 : International Relations / Prelims	प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया, भारत-रूस साझेदारी की सराहना की और पश्चिमी प्रतिबंधों की धमकियों के बीच पुतिन की यात्रा मोदी सरकार के लिए तनावपूर्ण कदम है
Page 04 Syllabus : GS 3 : Environment / Prelims	वन्यजीव निकाय बीएनएचएस 2026 में असम में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिर्दों को छोड़ेगा
Page 06 Syllabus : GS 2 : Governance / Prelims	डाक विभाग पतों के लिए यूपीआई जैसे 'लेबल' पर विचार करता है
Page 07 Syllabus : GS 2 : Social Justice	बच्चों में एचआईवी संचरण का एक चिंताजनक पैटर्न
Page 10 Syllabus : GS 1 : Society & Geography	चीन की ग्रामीण पुनरोद्धार की कहानी
Page 08 : Editorial Analysis	नई दिल्ली का सापेक्ष अलगाव, आतंक के साथ भारत का प्रयास



- प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत स्वागत और गर्मजोशी से अभिवादन एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारी की निरंतरता का संकेत देता है।
- यह इशारा भारत के रुख को रेखांकित करता है कि द्विपक्षीय संबंध पश्चिमी दबावों से तय नहीं होंगे।
- हालांकि, सरकार को प्रकाशिकी का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि भारत एक साथ बातचीत कर रहा है:
 - भारत-यूरोपीय संघ एफटीए
 - भारत-अमेरिका एफटीए
 - गणतंत्र दिवस और रणनीतिक संवादों के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेताओं की उच्च स्तरीय यात्राएं

भारत की "मल्टी-वेक्टर कूटनीति" और "रणनीतिक स्वायत्तता" की खोज को प्रदर्शित करता है।

2. रक्षा सहयोग: धूरी के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

- दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठकों ने निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया:
 - संयुक्त विकास
 - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
 - रक्षा में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना
- रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा भागीदार बना हुआ है, विशेष रूप से:
 - एस-400 सिस्टम
 - पनडुब्बी प्रौद्योगिकियां
 - विमान के इंजन
- रूसी ऊर्यूमा ने हाल ही में RELOS लॉजिस्टिक समझौते को मंजूरी दे दी, जिससे गहरे संयुक्त सैन्य अभ्यास की अनुमति मिली, जिसकी यूरोप ने पहले आलोचना की है।

महत्वपूर्ण बिंदु: रूसी तकनीकी हस्तांतरण बेजोड़ है; पश्चिमी देश शायद ही कभी उच्च अंत रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करते हैं।

3. ऊर्जा और व्यापार: प्रतिबंधों को नेविगेट करना और आयात को पुनर्संतुलित करना

- भारत का रूसी तेल का आयात 2022 से पहले 2% से बढ़कर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% हो गया.
- बढ़ती अमेरिकी जांच और प्रतिबंधों के कारण, भारत कच्चे तेल के आयात को कम कर सकता है, उनकी जगह ले सकता है:



- रूसी वस्तुएं
- उर्वरक
- कोकिंग कोल
- धातुओं
- द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर से बढ़कर 68.7 अरब डॉलर हो गया, लेकिन रूस के पक्ष में यह काफी असंतुलित है।
- चर्चाओं में शामिल हैं:
 - खाद्य, परिधान, मशीनरी के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना
 - पूर्वी समुद्री गलियारे (वेन्ट्रल-प्लादिवोस्तोक) का संचालन
 - भारत-ईर्झ्यू एफटीए पर प्रगति

भारत भू-राजनीतिक जोखिम के प्रबंधन के लिए व्यापार विविधीकरण का उपयोग कर रहा है।

4. श्रम गतिशीलता समझौता: एक नया रणनीतिक मोर्चा

- शिखर सम्मेलन का केंद्रबिंदु होने की उम्मीद है।
- रूस को 3.1 मिलियन श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर में:
 - वाक्य-रचना
 - निर्माण
 - टेक्नोलॉजी
- पश्चिम में आव्रजन नियमों को कड़ा करने के कारण भारत नए श्रम बाजारों की तलाश कर रहा है।

महत्व: कुशल/अर्ध-कुशल भारतीयों के लिए सॉफ्ट पावर, प्रेषण और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है।

5. परमाणु और उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग

- रूस के रोसाटॉम के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर बातचीत तेज हो गई है।
- भारत पांच स्वदेशी एसएमआर पर विचार कर रहा है, जिसमें रूस और यूरोपीय संघ दोनों देश भागीदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- परमाणु सहयोग भारत-रूस संबंधों का एक स्थिर और कम विवादास्पद क्षेत्र बना हुआ है।



समाप्ति

राष्ट्रपति पुतिन की राजकीय यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की निरंतर खोज को दर्शाती है - पुरानी साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ पश्चिम के साथ संबंधों का विस्तार करना। जबकि शिखर सम्मेलन भारत-रूस रक्षा, ऊर्जा, श्रम और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करता है, यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ आगामी संबंधों को देखते हुए सावधानीपूर्वक राजनयिक संतुलन की भी मांग करता है। भारत के लिए, चुनौती इस ऐतिहासिक साझेदारी को अधिक आर्थिक रूप से संतुलित, तकनीकी रूप से उन्नत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों में बदलने में है, बिना भू-राजनीतिक दबावों को अपने व्यापक विदेश नीति उद्देश्यों को पटरी से उतारने की अनुमति दिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

एक. भारत और रूस एक औपचारिक अंतर-सरकारी व्यवस्था के तहत एक वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं।

दो. भारत यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत कर रहा है।

तीन. भारत 2024-25 तक अपने कच्चे तेल का 40% से अधिक रूस से आयात करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2B. 2 और 3 केवलC. 1 और 3 केवलD. 1, 2 और 3

उत्तर: d)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन की 2025 की यात्रा के दौरान उजागर किए गए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करें और रूस और पश्चिम के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें। (150 शब्द)



Page 04 : GS 3 : Environment / Prelims

भारत के प्रमुख वन्यजीव अनुसंधान संगठन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) ने घोषणा की है कि जनवरी 2026 में असम के जंगल में छह गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों- पतले-चोंच वाले और सफेद दुम वाले गिद्धों को छोड़ दिया जाएगा। यह भारत के गिद्ध रिकवरी कार्यक्रम में एक बड़ा कदम है, जो दशकों से डाइक्लोफेनाक विषाक्तता के कारण जनसंभ्वा दुर्घटना के बाद है। यह पहल गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना (2020-2025) और भारत के दीर्घकालिक जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप है।



Wildlife body BNHS to release 6 critically endangered vultures in Assam in 2026

Purnima Sah
MUMBAI

The Bombay Natural History Society (BNHS), which has successfully bred more than 800 vultures in its conservation breeding centres across India, is now preparing to release six vultures in Assam in January 2026.

BNHS scientists on Thursday said they are finalising the dates to release three male and as many female slender-billed and white-rumped vultures, aged between two and three years, in Assam's Kamrup and Biswanath districts. They were bred at BNHS Vulture Conservation Breeding Centre in Rani, Kamrup district.

About the selection of Kamrup and Biswanath districts as the location to release the vultures, BNHS Senior Scientist and Assistant Director Dr. Sachin Ranade explained, "These locations fall within the natural range of vultures where there are already a



White-rumped vulture at BNHS Vulture Conservation Breeding Centre in Kamrup district. SPECIAL ARRANGEMENT

small flock of them and Biswanath is closer to Kaziranga National Park."

"The vultures will be kept there for a minimum of three months to experience the surrounding nature and adapt. During this time, they will observe other scavengers and become familiar with the environment. Since they have been bred in captivity – even though the enclosures are large – this will be their first experience of

true wilderness."

"Vultures live in flocks, attain maturity after the age of five, and can live up to 50 to 60 years. They have high immunity and do not easily catch infections or diseases," the BNHS scientists said. The founder stock (parents of these vultures) was collected from different parts of Assam. Dr. Ranade said the slender-billed vulture is mainly found in Assam, whereas white-

rumped vultures are found across India.

Currently, India is home to about 20,000 vultures across nine species, including bearded vulture, griffon vulture, and cinereous vulture.

The endangered species are the Egyptian vulture and the Himalayan griffon vulture, while the critically endangered species include the red-headed vulture, white-rumped vulture, long-billed vulture, and slender-billed vulture.

The scientists are working with local communities to save vultures in their natural habitats. The BNHS team, supported by the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) and the Assam Forest Department, has been working for over 15 years to prepare the ground for the release.

They are conducting village-level meetings and educating villagers about vultures and their importance.

प्रमुख बिंदु और विश्लेषण

1. यह रिलीज़ क्यों मायने रखती है

- 2-3 वर्ष की आयु के छह गिर्दों (3 नर + 3 मादा) को बीएनएचएस गिर्द संरक्षण प्रजनन केंद्र, रानी (कामरूप जिला) में पाला गया था।
- यह 15-1990 के दशक में 95% से अधिक के पतन के बाद गिर्दों की आबादी को पुनर्जीवित करने के 2000+ साल के प्रयास का हिस्सा है।

2. कामरूप और विश्वनाथ क्यों?

- ये जिले दो प्रजातियों की प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं।



- उनके पास पहले से ही छोटे मौजूदा गिर्द झुंड हैं।
- बिश्वनाथ जिला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के करीब है, जो एक प्रमुख पारिस्थितिक निवास स्थान है।

पारिस्थितिक महत्व: मौजूदा झुंड वाले क्षेत्रों में कैटिव-नस्ल के व्यक्तियों को जारी करने से सामाजिक व्यवहार और खाद्य स्रोत की उपलब्धता के कारण जीवित रहने की सफलता बढ़ जाती है।

3. रीवाइलिंग प्रक्रिया

- गिर्दों को कम से कम 3 महीने तक सॉफ्ट-रिलीज बाड़ों में रखा जाएगा।
- वे करेंगे:
 - प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल बनें,
 - अन्य मैला ढोने वालों का निरीक्षण करें,
 - खिलाने के संकेत सीखें,
 - विविध मौसम स्थितियों के अनुकूल।
- गिर्द 5 साल में परिपक्व होते हैं और 50-60 साल तक जीवित रह सकते हैं।

यह चरणबद्ध रीवाइलिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गिर्द कैद में पैदा हुए थे।

4. भारत में गिर्द की स्थिति

भारत में नौ प्रजातियों में ~20,000 गिर्द हैं, जिनमें शामिल हैं:

- गंभीर रूप से लुप्तप्राय:
 - सफेद दुम वाला गिर्द
 - लंबे चोंच वाला गिर्द
 - पतले चोंच वाला गिर्द
 - लाल सिर वाला गिर्द
- संकटग्रस्त:
 - मिस्र का गिर्द
 - हिमालयन ग्रिफॉन



जारी की जा रही दो प्रजातियां (पतली-चोंच वाली और सफेद दुम वाली) सबसे अधिक खतरे में हैं।

गिद्ध की स्टोन मैला ढोने वाले होते हैं; उनकी गिरावट के कारण जंगली कुत्तों में वृद्धि हुई और रेबीज का प्रसार हुआ।

5. बीएनएचएस, आरएसपीबी और असम वन विभाग की भूमिका

- बीएनएचएस ने अपने केंद्रों में 800+ गिद्धों को पाला है।
- रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स (RSPB) द्वारा समर्थित।
- व्यापक सामुदायिक आउटरीच जारी है:
 - गांव की बैठकें,
 - पशुधन में डाइक्लोफेनाक के उपयोग से बचने के बारे में जागरूकता,
 - गिद्ध-सुरक्षित क्षेत्र बनाना।

महत्व: संरक्षण स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

समाप्ति

असम में छह गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों की रिहाई की योजना भारत की गिद्ध संरक्षण रणनीति में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सफल एक्स-सीटू प्रजनन, मजबूत वैज्ञानिक योजना और बीएनएचएस, आरएसपीबी और असम वन विभाग के बीच सहयोग को दर्शाता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह पूर्वी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों की आबादी के पुनरुद्धार में तेजी ला सकता है, जिससे भारत की व्यापक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूती मिल सकती है।



UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : भारत में गिद्ध संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- एक. पतले चोंच वाला गिद्ध केवल असम में पाया जाता है।
दो. सफेद दुम वाले गिद्ध को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
तीन. गिद्ध जलदी परिपक्व हो जाते हैं, आमतौर पर दो साल की उम्र तक।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2B. 2 केवलसी। 1 और 3 केवलD. 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : गिद्ध संरक्षण के लिए भारत की कार्य योजना (2020-25) का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। गिद्धों की आबादी को उनके ऐतिहासिक स्तर पर बहाल करने में क्या चुनौतियाँ बनी हुई हैं? उपाय सुझाएं। (150 शब्द)



Page : 06 : GS 2 : Governance/ Prelims

डाक विभाग ने डाकघर अधिनियम, 2023 में एक संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें ध्रुव (डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस) नामक एक परिवर्तनकारी डिजिटल एड्रेसिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है। इस प्रणाली का उद्देश्य लंबे पाठ्य पतों को UPI-शैली के डिजिटल एड्रेस लेबल (जैसे, name@entity) के साथ बदलकर, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉर्मर्स दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में काफी सुधार करके भारत के एड्रेसिंग आर्किटेक्चर को आधुनिक बनाना है। यह भारत के व्यापक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बढ़ावा देने का हिस्सा है।

Postal department considers UPI-like 'labels' for addresses

The system, called DHRUVA, will provide users a convenient way to share their addresses across platforms; users can grant firms limited address access, after which the label needs re-authorisation

Aroon Deep
NEW DELHI

The Department of Posts this week released a draft amendment to the Post Office Act, 2023, aimed at introducing an interoperable, standardised, and user-centric addressing system called the Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address, or DHRUVA. The framework has been under consultation for a few months, with one key element, DIGIPIN, rolled out in March.

A senior official involved in DHRUVA's implementation said it would be able to replace textual addresses with email or UPI address-like labels such as "name@entity", which would act as a proxy for a physical address.

The government hopes to build this system as part of its digital public infrastructure initiatives and will allow private companies to participate.

The department is hoping to draw interest from e-commerce and gig platforms, where users need to provide addresses across

Smart addresses

A draft amendment seeks to enable an interoperable system replacing physical addresses with smart labels like "name@entity" powered by DIGIPIN for precise geolocation

- Labels will be provided by address service providers, while consent architecture will be managed by address information agents
- It will be based on the DIGIPIN system, which is a 10-character alphanumeric expression of latitude and longitude coordinates



- The technology was developed to provide more precise locations in rural areas or in cases where the textual expression of a physical address does not offer adequate information
- The draft amendment is under consultation; Section 8 entity proposed (like NPCI for UPI)
- The system will be built as part of government's digital public infrastructure initiatives, and will allow private firms to participate

in the draft amendment for private players to join, the official said, and the department hopes the system will be compelling enough for firms and users to sign up.

Labels will be provided by address service providers, and the consent architecture will be managed by address information agents, or AIAs.

DIGIPIN system

The DIGIPIN system is the foundational layer for this service, the official said. DIGIPIN is a 10-character alphanumeric expression of latitude and longitude. The technology was developed to provide more precise locations in rural areas or in cases where the textual expression of a physical address does not offer adequate information.

DIGIPIN was open-sourced by the department, and each DIGIPIN corresponds to a roughly 14 square metre patch of land, with a mathematical function deterministically generating a unique code. This translates to around 228 billion DIGIPINs for Indian territory.

multiple services. On these platforms, individuals would be able to provide a label instead of an address and authorise firms to receive the geographic coordinates and full text of their address instantly, instead of filling out address forms repeatedly.

The draft amendment would allow the postal department to set up a Section 8 not-for-profit entity under government supervision. The body would

play a role similar to the National Payments Corporation of India, which is an association of banks administering the UPI payments system.

Consent-based

Users would be able to authorise companies to view their address for a specified period if they wish, after which a given label will require re-authorisation.

There is no compulsion

प्रमुख बिंदु और विश्लेषण

1. ध्रुव क्या है?



- एक इंटरऑपरेबल, मानकीकृत, उपयोगकर्ता केंद्रित डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम।
- ईमेल आईडी या UPI हैंडल जैसे कार्य: उदाहरण: abhay@india एक पूर्ण भौतिक पते का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता ई-कॉमर्स, गिग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर बार-बार विस्तृत पते भरने के बजाय इस लेबल को साझा कर सकते हैं।

2. सहमति-आधारित पता साझा करना

- उपयोगकर्ता कंपनियों को ध्रुव लेबल के माध्यम से तुरंत पूर्ण पते का विवरण या भू-निर्देशांक पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं।
- पहुंच है:
 - समयबद्ध,
 - सहमति आधारित,
 - समाप्ति के बाद पुनः प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

महत्व: डेटा गोपनीयता को मजबूत करता है, न्यूनतम डेटा साझाकरण सुनिश्चित करता है।

3. संस्थागत संरचना

- संशोधन प्रणाली को चलाने के लिए एनपीसीआई के समान धारा 8 (गैर-लाभकारी) इकाई के निर्माण को सक्षम बनाता है।
- निजी खिलाड़ी (जैसे अमेज़ॅन, ज़ोमैटो, स्क्वारी, डंजो) स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं।

नोट: सरकार को उम्मीद है कि सुविधा के कारण प्रणाली व्यवस्थित रूप से लोकप्रिय हो जाएगी।

4. एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर और एआईए

- पता सेवा प्रदाता (ASP): डिजिटल लेबल (UPI-जैसे हैंडल) जारी करें।
- पता सूचना एजेंट (एआईए): उपयोगकर्ता की सहमति और डेटा प्रवाह प्रबंधित करें।

यह UPI के PSP और TPAP की संरचना को प्रतिबिंబित करता है → वितरित शासन + इंटरऑपरेबिलिटी है।

5. डिजिपिन: तकनीकी कोर

- DIGIPIN = अक्षांश + देशांतर का प्रतिनिधित्व करने वाला 10-वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड।
- सटीकता: ~ 14 वर्ग मीटर प्रति कोड।
- पूरे भारत में 228 बिलियन यूनिक डिजीपिन संभव हैं।
- सटीक ग्रामीण पतों या अनौपचारिक बस्तियों को संबोधित करने के लिए विकसित।

अर्थ:

- आपातकालीन सेवाओं, जनगणना, वितरण सेवाओं, लोक कल्याण योजनाओं में मदद करता है।
- ओपन-सोर्स: पारदर्शिता और नवीनता सुनिश्चित करता है।

6. यह भारत के लिए क्यों मायने रखता है

- भारत दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों (असंरचित पते, भाषा विविधता) का सामना कर रहा है।
- ध्रुव करेगा:
 - वितरण विफलताओं को कम करें,
 - ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में सुधार करें,



- सेवा वितरण में तेजी लाएं,
- शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में सहायता करना,
- शासन के लिए भू-स्थानिक परिशुद्धता को सक्षम करें।

समाप्ति

ध्रुव डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य पतों को इंटरऑपरेबल, स्टीक और सहमति-आधारित बनाना है। डिजिपिन के जियो-कोडेड इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित यूपीआई जैसे वर्चुअल लेबल का उपयोग करके, डाक विभाग लंबे समय से चली आ रही लॉजिस्टिक और प्रशासनिक चुनौतियों को हल करने के लिए भारत को तैयार कर रहा है। यदि व्यापक रूप से अपनाया जाता है, तो ध्रुव आने वाले दशक में शासन, आर्थिक गतिविधि और डिजिटल सेवाओं के लिए एक मूलभूत परत बन सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: डाक विभाग द्वारा हाल ही में प्रस्तावित ध्रुव प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य पाठ्य भौतिक पतों को इंटरऑपरेबल डिजिटल एड्रेस लेबल से बदलना है।
2. सभी निजी ई-कॉर्मस प्लेटफॉर्म के लिए सिस्टम में शामिल होना पूरी तरह से अनिवार्य है।
3. यह भू-निर्देशांक को एन्कोड करने के लिए DIGIPIN नामक 10-वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड का उपयोग करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : प्रस्तावित धरूवा डिजिटल एड्रेस प्रणाली में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रदायित व ढांचे को बदलने की क्षमता है। शासन दक्षता और नागरिक सशक्तिकरण में सुधार के लिए सहमति-आधारित डिजिटल पतों के महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Page 07 : GS 2 : Social Justice



एचआईवी की रोकथाम और मातृ स्वास्थ्य देखभाल में प्रमुख प्रगति के बावजूद, मां से बच्चे में संचरण (एमटीसीटी) एक महत्वपूर्ण वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। एक चिंताजनक पैटर्न उभरा है: शिशु एचआईवी के लिए सकारात्मक परीक्षण कर रहे हैं, भले ही उनकी माताओं ने गर्भावस्था के दौरान नकारात्मक परीक्षण किया हो। यह घटना, जिसे "साइलेंट ट्रांसमिशन गैप" के रूप में जाना जाता है, एचआईवी परीक्षण के समय, आवृत्ति और अनुवर्ती में महत्वपूर्ण कमजोरियों को प्रकट करती है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

1. एचआईवी मां से बच्चे में कैसे फैलता है

एचआईवी फैल सकता है:

- गर्भावस्था के दौरान (गर्भाशय में),
- प्रसव के दौरान,
- स्तनपान के दौरान।

बेहतर प्रसवपूर्व परीक्षण और एआरवी थेरेपी ने विश्व स्तर पर संचरण को कम कर दिया है, लेकिन अंतराल बना हुआ है।

2. माताओं के नकारात्मक परीक्षण होने पर भी शिशुओं को एचआईवी क्यों होता है

a) गर्भावस्था के दौरान नए मातृ संक्रमण: कई महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में नकारात्मक परीक्षण करती हैं, लेकिन बाद में एचआईवी प्राप्त करती हैं, जब वायरल लोड सबसे अधिक होता है, जिससे संचरण का खतरा तेजी से बढ़ जाता है।

बी) विंडो अवधि: "विंडो पीरियड" एचआईवी संक्रमण के बाद प्रारंभिक चरण है जब वायरस मौजूद होने के बावजूद मानक परीक्षण नकारात्मक हो सकते हैं। एक महिला नकारात्मक परीक्षण कर सकती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक संक्रमण हो सकती है।

ग) एकल-परीक्षण प्रोटोकॉल: अधिकांश कार्यक्रम प्रारंभिक गर्भावस्था में केवल एक एचआईवी परीक्षण की सलाह देते हैं। इसमें कोई नियमित दोहराव परीक्षण नहीं:

- देर से गर्भावस्था,
- डिलीवरी के समय,
- स्तनपान की अवधि।

यह नए अधिग्रहित संक्रमणों को अनियंत्रित करने की अनुमति देता है।

3. यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता क्यों है



Cause for concern: HIV can pass from a mother to her baby during pregnancy, during delivery, or through breastfeeding; norovirus

Amol Jaybhaye

Mother-to-child transmission of HIV remains one of the major challenges in the fight against HIV/AIDS. HIV can pass from a mother to her baby during pregnancy, during delivery, or through breastfeeding. In many countries, early antenatal HIV testing, treatment for pregnant women living with HIV and immediate postnatal testing has reduced transmission rates across many regions. However, an important concern continues to be the "silent transmission gap". Some babies are still diagnosed with HIV even though their mothers tested negative during pregnancy. This worrying pattern, often called the silent transmission gap, highlights key gaps in testing, timing and follow-up.

Many women test negative in early pregnancy, but may become infected during pregnancy, her viral load is often very high, which greatly increases the chance of transmission. In the baby, a single test at the start of pregnancy may therefore miss new infections that happen later.

After birth, there is an interval during which standard screening tests may not detect HIV even though the virus may have been transmitted. The risk of transmitting HIV is high. This means a pregnant woman may test negative despite being infected.

Usually, only one HIV test is recommended during the early stages of pregnancy, unless there is a clinical need.

Some babies are still diagnosed with HIV even though their mothers tested negative during pregnancy. This worrying pattern is often called the silent transmission gap.

Within the last few years of pregnancy and during breastfeeding, some babies have a high chance of being undetected. This creates a missed opportunity for early treatment and prevention.

The risk of transmission is especially high during late pregnancy and during the breastfeeding period. Transmission can happen during delivery, during birth or after birth through breast milk.

What can be done?

To close this silent gap, the following steps are important:

For pregnant women: Repeat HIV testing in the later months of pregnancy, immediately after delivery and during breastfeeding can help to check for the infection. Additional testing may be needed if there is a clinical suspicion of recent exposure or symptoms.

For infants: Early virologic testing soon after birth and follow-up testing if needed can go a long way.

Prompt treatment must begin in case of a positive result.

Closing the gap

The occurrence of HIV in babies whose mothers test negative during pregnancy, indicates a significant gap in prevention, especially in low- and medium-HDI countries. Treatment failure in known HIV positive mothers, but mainly due to the occurrence of new maternal infections, short duration and a lack of repeat testing.

A few simple steps, such as enforcing repeat testing regulations, improving clinical follow-ups especially during pregnancy and delivery, and ensuring early infant testing will go a long way toward ensuring that essential steps are taken to close this gap.

Closing this silent transmission gap is crucial as part of the global effort to end the HIV in India.

Dr. Amol Jaybhaye is consultant -

paediatric infectious diseases, Narayana

Multi-Speciality Children's Hospital, Mumbai.

Info: www.narayanachildrens.org/



- मातृ संक्रमण छूटना → एआरटी की प्रारंभिक शुरुआत से चूक गए।
- देर से गर्भवस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उच्च शिशु संचरण जोखिम।
- छिपा हुआ बोझ बाल चिकित्सा एचआईवी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को कमजोर करता है।

4. क्या किया जा सकता है? (आगे की राह)

गर्भवती महिलाओं के लिए

- अनिवार्य दोहराने एचआईवी परीक्षणः
 - तीसरी तिमाही में,
 - डिलीवरी के समय,
 - समय-समय पर स्तनपान के दौरान।
- उच्च जोखिम वाले जोखिम या लक्षणों के लिए अतिरिक्त परीक्षण।

शिशुओं के लिए

- प्रारंभिक वायरोलॉजिकल परीक्षण (जन्म के तुरंत बाद पीसीआर-आधारित परीक्षण)।
- जहां आवश्यक हो अनुवर्ती परीक्षण दोहराएं।
- एचआईवी पॉजिटिव शिशुओं के लिए उपचार की तत्काल शुरुआत (प्रारंभिक एआरटी उत्तरजीविता में काफी सुधार करती है)।

प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण

- दोहराने परीक्षण पर प्रोटोकॉल लागू करें।
- प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर अनुवर्ती को मजबूत करें।
- नए संक्रमणों और विंडो पीरियड्स के बारे में सामुदायिक परामर्श और जागरूकता को एकीकृत करें।

समाप्ति

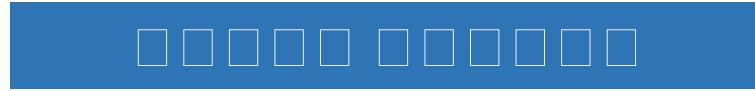
गर्भवस्था के दौरान माताओं के नकारात्मक परीक्षण के बावजूद शिशुओं में एचआईवी संक्रमण में वृद्धि भारत और वैश्विक एचआईवी-रोकथाम रणनीतियों में एक मूक लेकिन रोकथाम योग्य अंतर को उजागर करती है। मुद्दा ज्ञात एचआईवी पॉजिटिव माताओं में उपचार की विफलता नहीं है, बल्कि नए मातृ संक्रमण का पता लगाने में विफलता है। इस अंतर को बंद करने के लिए बार-बार परीक्षण को मजबूत करना, नैदानिक अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार करना और प्रारंभिक शिशु निदान सुनिश्चित करना आवश्यक है। बच्चों में एचआईवी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण है।



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

UPSC Mains Practice Question

गर्भवस्था के दौरान माताओं के नकारात्मक परीक्षण के बावजूद शिशुओं में एचआईवी संक्रमण का बढ़ना भारत की मातृ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एक मूक संचरण अंतर को प्रकट करता है। इस अंतर के पीछे के कारणों पर चर्चा करें और एचआईवी के मां से बच्चे में संचरण को खत्म करने के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)



Page 10 : GS 1 : Society & Geography

जैसे-जैसे चीन अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के करीब पहुंच रहा है - जिसे 2035 तक समाजवादी आधुनिकीकरण प्राप्त करने के लक्ष्य के "समेकन और पूर्ण कार्यान्वयन चरण" के रूप में परिकल्पित किया गया है - गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण पुनरोद्धार पर इसके दीर्घकालिक कार्यक्रम महत्वपूर्ण परिणाम दिखाने लगे हैं। लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लक्षित राज्य हस्तक्षेप, बड़े सार्वजनिक निवेश और सामुदायिक भागीदारी ने पश्चिमी और मध्य चीन में दूरदराज के ग्रामीण काउंटीयों को बदल दिया है।

China's story of rural revitalisation

As China prepares to enter into its 13th five-year plan, considered to be the consolidation and full implementation¹ period of the goal to realise Socialist modernisation by 2035, the efforts taken up by the administration for poverty alleviation and rural revitalisation are showing results.

WORLD INSIGHT

Vishalakshi V. Jayakrishnan

Chinese President Xi Jinping, who has visited every one of the country's 830 counties in his first year as president, believes that the Communist Party of China (CPC), in 2022, had made that eradication of poverty and improving people's livelihoods are the top priorities of the government. He had called for close attention to people in "poor circumstances", noting that "with no one left behind, we can truly be termed 'no-poor'". The people of the Xiangxiang village in Hunan province, which was earlier declared 'poor', said this confidence to turn over gold the "yellow earth", taking pride over their remarkable progress in the last decade, when they built houses, roads with their bare hands, over the years, facing poverty and improving living conditions.

A stark divide?
China is a land of diversity. The country runs by the CPC under principles of "Socialism with Chinese characteristics" has embraced market economy and state-led capitalism, which can be seen in the rapid urbanisation, its focus on its economic base and brands, both strong and local, competing for global markets. It has adopted the classic panaceian style of Shanghai and Shenzhen, the strategic and pragmatic choices of Beijing, options of the countryside and the rural modernisations to rule at the core of the country's economy, in contrast to the rest of the world, which follows the laissez-faire model. As China prepares to enter into its 13th five-year plan, considered to be the consolidation and full implementation¹ period of the goal to realise socialist modernisation by 2035, the efforts taken up by the administration for poverty alleviation and rural revitalisation are showing results.

The Chinese leadership has decided to focus development and modernisation with the eastern coastal areas, which have been the pillars of the economy, while the inland and rural areas have been left out. This is changing. Gaoming with special economic zones in Shenzhen and Shantou which were established in 1980, as the first special economic zone, is the first to move forward, and now the central and provincial-level cities like Beijing and Shanghai are also moving forward. But if one moves into the hinterland or into the rural areas, one finds that the landscape has changed so much as to change.

The progress of poverty programmes in Sichuan, bordering the borders of India, Bangladesh, the heart of China and Myanmar, bordering Vietnam and Myanmar, one can see long winding roads, which are not paved, and the roads are narrow. These towns are on an entirely different plane of existence when compared to the cities of the coastal areas. Adorned with lush mountainous and cloud forests, when in the words of Dr. N. R. Narayana Murthy, the chairman of Infosys, "the road to heaven and hell passeth in these towns".

The Chinese government imposed an modernisation and development during the decades following the opening up policy of Deng Xiaoping. During Deng Xiaoping, poverty alleviation has also received its fair share of attention. Special poverty relief funds were set



Basic needs: A modern facility in a rural area in Sichuan province, China.

THE GIST

What is new: China's shifting paradigm of development, where the absence of Beijing's strict control of development has led to a more diversified economy. It can now be a part of the world's growth story.

While the Chinese government does not believe in a centrally planned economy, it has adopted a developmental approach, driven by the opening up of its economy, and the rural areas have been given a shot in the arm.

In 2020, after 8 years, the central government of CPC declared the final outcome of the rural revitalisation plan which aims at ending extreme poverty by 2021.

up across the country in phases, eliminating poor counties, and drawing attention to poverty alleviation measures.

A total of 273 counties were initially listed as poverty-stricken, which later rose to 285 in 1998. A successive programme for lifting 80 million rural people out of poverty was initiated in 1994. This was followed by the outline for development-oriented poverty alleviation, which targeted rural areas in 2000.

The author noted that while the number of extreme poverty-stricken households in the rural areas had reduced by 90%, there was an increase in the number of households in central and western areas. Between 2000 and 2010, poverty headcount ratio dropped to 3.6% from 22.3% and the number of households in key counties saw an average of 37%.

From a poor and backward, the Malozi and Jinyang in Yunnan and Baishui in Sichuan, which are mountainous and hilly areas, the poverty-stricken areas, development has had to take the long road. However, they show resilience, and through their accessibility and sustainability, windmills sprang up on high hill tops which generate electricity and provide a common light along the roads in these areas. Solar powerplants were made by the local areas being around in remote areas, and the government has invested in them and the main income was seen for the village.

The government under its poverty reduction and alleviating programmatic component, established in 2005, runs basic education, health care, and in the collection and processing of the tea leaves. According to Yuan Tie, Head of the county, tea is the main product in the county and is exported to countries like France, Japan, and Russia. The tea plantation project has already started along with 2.5 million rupee investments from the provincial government and the local municipality.

an example of rural poverty alleviation model achieved developed regions from eastern China and investments and human resources to aid the rural areas. The total investment of the corporation stands at 160,000 to 180,000 million rupees, with the village committee getting a share which is distributed to the villages where the tea is produced, which is approximately 30,000 rupees per year, says Mr. Xu, the Minister of Foreign Affairs has also added that the tea is sold to a tea processing factory with interest free loans, he says.

Other poverty alleviation measures having shown results in improving basic living condition, China is already shifting towards a more diversified economy. In January this year, the central committee of the CPC released the 14th five-year plan, which aims at making it highly efficient major rural areas by 2035. It focuses on the rural areas to improve the society's food security while broadening the property of rural communities, closing the gap between the rich and the poor, developing infrastructure.

Other than the extreme poverty and rural areas, the states and China remain in the spirit of people travelling along the expressways built by the government. The expressways make the villages look more and the realisation comes that the will of the people is reflected in the government's role played in building up the soils.

The writer is the Chair of the Institute of the China Public Diplomacy activities.



प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

1. गरीबी उन्मूलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चीन में संस्थागत गरीबी में कमी का एक लंबा प्रक्षेपवक्र है:

- 1986: विशेष गरीबी राहत संस्थानों का गठन किया गया। 273 गरीब काउंटियों की पहचान की गई।
- 1994: 80 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सात साल का कार्यक्रम।
- 2001: विकासोन्मुखी गरीबी उन्मूलन रूपरेखा ने ग्रामीण पुनर्गठन पर जोर दिया।
- 2001-2010: गरीबी के मामलों की संख्या 10.2% से गिरकर 3.8% हो गई, ग्रामीण आय में सालाना 7.6% की वृद्धि हुई।
- 2020: चीन ने घोषणा की कि उसने अत्यधिक ग्रामीण गरीबी को समाप्त कर दिया है।

राज्य के नेतृत्व वाले विकास + लक्षित कल्याण + दीर्घकालिक योजना को दर्शाता है।

2. शहरी-ग्रामीण और क्षेत्रीय विभाजन

चीन एक आश्वर्यजनक द्वंद्व प्रदर्शित करता है:

- पूर्व (गुआंगडोंग, शंघाई, बीजिंग):
 - वैश्वीकृत, औद्योगिक, विश्व बाजारों के साथ एकीकृत
 - शेन्ज़ेन और झुहाई जैसे एसईजेड का घर
- मध्य और पश्चिमी क्षेत्र (सिचुआन, युनान):
 - पहाड़ी, कम आबादी वाला, ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग
 - धीमा विकास, सीमित कनेक्टिविटी

ग्रामीण पुनरोद्धार के प्रयास इस शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो शी जिनपिंग के शासन दर्शन के तहत एक मुख्य सीपीसी प्राथमिकता है।

3. दूरदराज के क्षेत्रों में विकास: बुनियादी ढांचा और स्थिरता

सिचुआन, युनान, मालिपो, जिनपिंग और पंजिहुआ के उदाहरण दिखाते हैं:

- सड़कों, पवन ऊर्जा और पारिस्थितिक परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश।
- उच्च श्रेणियों पर पवन चक्रियां, हरित आवरण बहाली, जल संरक्षण।



- सरकार स्थानीय रोजगार सृजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है।

मालिपो काउंटी का मामला:

- 99% पहाड़ी
- वार्षिक प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय अब 9,000 आरएमबी
- से सहायता:
 - विदेश मंत्रालय (1992 से)
 - प्रांतीय सरकार
 - राज्य द्वारा वित्त पोषित उद्यम

यह चीन के "साझा समृद्धि" और राज्य-संचालित क्षेत्रीय समानता के मॉडल से जुड़ा हुआ है।

4. स्थानीय समुदायों की भूमिका: 'ज़िचौ आत्मा'

लोगों की भागीदारी को आवश्यक के रूप में रेखांकित किया गया है:

- निवासियों ने ज़िचौ में बंजर चट्टानी भूमि को हरे उत्पादक स्थानों में बदल दिया - जिसे "ज़िचौ आत्मा" कहा जाता है।
- जिनपिंग काउंटी में जिवोझाई गांव की प्राचीन चाय सहकारी (स्था. 2014):
 - 800 साल पुराने चाय के पेड़ों को संसाधित करता है
 - फ्रांस, जापान, वियतनाम को निर्यात
 - द्वारा समर्थित:
 - युनान और शंघाई से 2.8 मिलियन आरएमबी निवेश (अंतर-प्रांतीय सहायता मॉडल)
 - विदेश मंत्रालय से ब्याज मुक्त ऋण
 - घरेलू आय लगभग 30,000 आरएमबी/वर्ष

यह चीन के सामूहिक उद्यम + राज्य की पूँजी + सहकारी शासन के मिश्रित मॉडल का संकेत देता है।

5. ग्रामीण पुनरोद्धार की ओर बदलाव (गरीबी के बाद का युग)

चीन का नया फोकस:



- जनवरी 2025: CPC ने ग्रामीण व्यापक पुनरोद्धार योजना (2025-2027) की घोषणा की।
- उद्देश्यों:
 - कृषि उत्पादकता (खाद्य सुरक्षा) को मजबूत करना
 - शहरी-ग्रामीण आय अंतर कम
 - ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं का निर्माण
 - ग्रामीण उद्योगों (चाय, पर्यटन, हस्तशिल्प) को बढ़ावा देना
 - गरीबी सूची से हटाने के बाद जीवन स्तर को स्थिर करना

रणनीतिक महत्व: "गरीबी की ओर वापसी" को रोकता है और दीर्घकालिक ग्रामीण स्थिरता का समर्थन करता है।

समाप्ति

चीन की ग्रामीण पुनरोद्धार कहानी राज्य के नेतृत्व वाले, लंबी दूरी, संस्थागत रूप से समर्थित विकास के एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है, जहां बुनियादी ढांचा, पारिस्थितिकी, गरीबी में कमी और सामुदायिक भागीदारी अभिसरण करती है। जबकि बड़ी क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई हैं, चीन के उदाहरण से पता चलता है कि कैसे निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता, केंद्रीय योजना और स्थानीय लामबंदी दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों को उत्पादक, आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में बदल सकती है। यूपीएससी के लिए, यह विकास रणनीतियों, ग्रामीण परिवर्तन, सहकारी शासन और गरीबी उन्मूलन मॉडल में मजबूत तुलनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : चीन का ग्रामीण पुनरोद्धार मॉडल राज्य के नेतृत्व वाले विकास, सामुदायिक भागीदारी और दीर्घकालिक योजना के मिश्रण को दर्शाता है। चर्चा करना। (150 शब्द)



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Page : 08 : Editorial Analysis



New Delhi's relative isolation, India's tryst with terror

The current period might well be viewed, or termed, as India's moment of reckoning. For one, India today – and despite its highly regarded diplomatic skills – increasingly appears more like an 'outlier' than a major player in world affairs. It has been virtually sitting on the sidelines when it comes to issues involving peace and order in different regions of the globe, especially in West Asia and Europe. It is also a virtual onlooker as far as the emerging situation in the Indo-Pacific is concerned. Seldom indeed has India faced a situation of this kind.

If this was not bad enough, the entire South Asian region in which India is situated, appears to be in turmoil at present. Afghanistan and Nepal are among the countries on India's periphery that appear to be most affected, but from the Maldives to Myanmar and further afield, India can hardly count on many friends and allies. This is a frightening scenario given that each day produces a range of new threats, including cyber.

Hostility from west to east

Currently, India has to contend with two openly hostile powers on its western and eastern flanks – Pakistan and Bangladesh, respectively. In the case of Pakistan, the threat level has been going up steadily, with a growing cacophony of voices being heard in that country to teach India a proper lesson. What is aggravating the situation further is the approval of the 27th Constitutional Amendment Bill by Pakistan's Joint Parliamentary Committee of the Senate and National Assembly, which has altered the precarious balance between civil and military authority in that country.

Also, a recent amendment has introduced the concept of a new 'Chief of Defence Forces', elevating Field Marshal Asim Munir as the nation's military supremo, and the commander-in-chief of all three services, having sole control over Pakistan's nuclear assets. The amendment has invested Field Marshal Munir with absolute authority to deal with enemies (such as India), removing the fig leaf of parliamentary restraint and posing a real threat to India on its western flank. Military dictatorships in Pakistan, as elsewhere, have traditionally proved to be extremely hostile to a democratic India, and the rise and rise of Field Marshal Asim Munir, with unfettered authority, represents a significant and direct threat to a democratic India.

That such concerns are well merited, and that military dictators tend to be short sighted, is well known. Concentration of power encourages strategic adventurism. This, in turn, increases the chances of miscalculation in crises. Also, and in keeping with the general trend among military regimes, there is likely to be a tendency to turn local conflicts into spheres of proxy competition and inter-state confrontation. Hence, prospects of a lasting peace with Pakistan are unlikely. On the other hand, the risk of conflict has enhanced



M.K. Narayanan

is a former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

significantly. Thus, it would be wise for India not to ignore the possibility of yet another conflict with Pakistan in the near future and be prepared for all eventualities. This may as yet be in the realm of speculation, but the danger must not be ignored.

India's Pakistan problem is compounded by the fact that the interim government in Bangladesh to India's east, is proving unfriendly, if not openly hostile, to it. To add to India's discomfiture, Bangladesh is currently displaying a willingness to establish warmer relations with Pakistan. In a first, a Pakistan navy ship visited Bangladesh after almost a half-a-century and this is expected to help Pakistan re-establish its presence in the Bay of Bengal. This has serious security implications for India.

Hence, a mixture of ideological posturing and military governance on India's western and eastern flanks has raised diplomatic temperatures across the region. It could have serious and adverse consequences, if not properly handled. Extreme vigilance and careful manoeuvring is called for.

The surfacing of 'urban terror'

Compounding India's problems at this time is the return of 'urban terror' after a gap of several years, though in a different mould, and by a whole new set of indigenous actors. It is only fair to think that in the highly disparate world that we live in, and in the circumstances prevailing today, terror is merely a hand's length away from everyday existence. Yet, till recently, urban terrorism on a significant scale had taken a back seat after the 2008 terror attacks in Mumbai sponsored by Pakistan-based Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed in collusion with elements of the Pakistan military establishment.

During the past two decades, sporadic terror attacks had been reported in certain urban pockets, but the latest module of urban terror – extending from Jammu and Kashmir to Faridabad and Delhi, and involving medical practitioners and doctors (most of whom had connections to the Al-Falah university, Faridabad, Haryana) reveals a new chapter in India's tryst with terrorism.

The latest terror module, comprising almost only medical practitioners, draws inspiration from, and harps back to the destruction of the Babri Masjid in Ayodhya (in 1992). It fundamentally differs from the terror attacks witnessed in Mumbai (and certain other pockets) during 1992-1993 in the wake of the Babri Masjid demolition, which were mainly carried out by 'lumpen' elements.

That more than three decades after the destruction of the Babri Masjid, terror still finds supporters and that too among the educated elite. That is more so among groups, such as doctors, is highly disturbing. It reveals that religious terrorism is not only alive but still active.

Also, its newest disciples represent some of the best and brightest elements of a community. This

The country is having to deal with being an onlooker in world affairs, and also the fault lines in its multi-cultural, multi-religious society

is a quantitative and qualitative leap as far as the annals of terror are concerned.

Details of the terror module, which extends from Srinagar to Faridabad to Delhi, have been widely aired. But what should cause more serious and deep concern is that they could accumulate nearly 3,000 kilograms of explosive material and also safely hide it in two houses. Further, it is alarming that a car laden with explosives could escape the police dragnet around India's capital city, Delhi, and trigger an explosion in the vicinity of Red Fort in the heart of Delhi. This reveals either extremely careful planning at one level, or total ineptness on the part of the authorities, on another. Worse still, while the 1993 terror explosions were carried out by 'lumpen elements' and the 2008 Mumbai attacks were directly sponsored by Pakistan, the latest incidents were of an entirely different character.

These were organised by a group of medical professionals, some of whom were perhaps not even born when the destruction of the Babri Masjid took place, revealing a major fault line in India's multi-cultural, multi-religious society. Far more than the details of the terror module that are being revealed through painstaking investigation, it is this aspect, and the aspect of revenge, which has been the catalyst for some of the best and brightest in a community, which should be seen as a blot on India's civilisational journey and progress.

The moot point is whether the latest incident represents mere disenchantment and anger against the nation state, or something more fundamental. It has been India's belief, and as claimed by the Union Home Minister in Parliament, that no local had joined a terrorist group in Jammu and Kashmir in recent times.

This myth has been exploded. Investigations have revealed that this is an entirely local terrorist module, which had been using encrypted channels for indoctrination, coordination, fund movements and logistics. Another aspect is that funds were being raised by professional and academic networks under the guise of social/charitable causes. There are other reports that the groups were in touch with elements in Pakistan. The links of the group also seem to extend beyond Pakistan to the United Arab Emirates, Saudi Arabia and Turkey.

The need for vigil

Given the new perilous external dimension to India's security, a hostile Pakistan and Bangladesh on its western and eastern borders, and the fact that much of West and South Asia are in turmoil, India needs to be careful that the situation does not lead to the fostering of religious fascism on a more extended scale. Given India's tolerance and acceptance of disparate religious beliefs, this may seem unlikely. But eternal vigilance (or diligence) is the price that needs to be paid to ensure that the situation does not deteriorate further, necessitating cause for alarm.



GS-1 : Indian Society & Geography

UPSC Mains Practice Question : भारतीय शहर तेजी से जलवायु चरम सीमाओं के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं, और पारंपरिक शहरी नियोजन मेट्रिक्स इस नई वास्तविकता को पकड़ने में विफल हो रहे हैं। इस संदर्भ में, भारत के शहरी केंद्रों के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें और एक लचीले शहरी नियोजन ढांचे का सुझाव दें। (250 शब्द)

संदर्भ:

लेख में तर्क दिया गया है कि भारत एक चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक चरण में प्रवेश कर रहा है, जो रणनीतिक अलगाव, बिगड़ते पड़ोस के संबंधों और घरेलू 'शहरी आतंक' की एक नई लहर से चिह्नित है। लेखक, एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेतावनी देते हैं कि भारत एक साथ खतरों का सामना कर रहा है: अस्थिर पड़ोसी, पाकिस्तान में बढ़ता सैन्य प्रभुत्व, बांग्लादेश से शान्ति, और नए उभरते स्वदेशी आतंकवादी मॉड्यूल। स्थिति में सतर्कता बढ़ाने, राजनयिक पुनर्मूल्यांकन और घरेलू सामंजस्य की आवश्यकता है।

1. भारत का उभरता हुआ राजनयिक अलगाव

एक। भारत एक 'आउटलायर' के रूप में

- भारत की कूटनीतिक सक्रियता के बावजूद, यह शांति और संघर्ष पर प्रमुख वैश्विक वार्तालापों से तेजी से अनुपस्थित है।
- भारत को दरकिनार कर दिया गया है:
 - पश्चिम एशिया (इज़राइल-हमास संघर्ष, लाल सागर संकट)
 - यूरोप (यूक्रेन-रूस युद्ध)
 - इंडो-पैसिफिक (अमेरिका-चीन प्रतिवृद्धि, AUKUS, QUAD चुनौतियां)

भारत के बारे में यह धारणा "किनारे पर बैठे" एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी होने के उसके दावे को कमज़ोर करती है।

2. खतरनाक पड़ोस: दक्षिण एशिया में संकट

a. क्षेत्रीय उथल-पुथल

भारत के आसपास लगभग हर देश अस्थिर है:

- अफगानिस्तान: तालिबान शासन, चरमपंथी नेटवर्क
- नेपाल: राजनीतिक प्रवाह, चीन का बढ़ता प्रभाव
- मालदीव: भारत विरोधी बयानबाजी
- म्यांमार: गृहयुद्ध और शरणार्थी प्रवाह



इससे अपने निकटतम पड़ोस में भारत का प्रभाव कम हो गया है।

3. दोनों पक्षों से शत्रुता: पाकिस्तान और बांगलादेश

a. पाकिस्तान – बढ़ता सैन्य दुर्स्साहस

पाकिस्तान के खतरे की धारणा की वजह से बिगड़ रही है:

- सेना पर नागरिक नियंत्रण को कम करने वाला 27वां संविधान संशोधन विधेयक
- नए पद का सृजन: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज
- फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पास अब पूर्ण अधिकार है:
 - तीन सशस्त्र सेवाएं
 - परमाणु शस्त्रागार
 - युद्ध और संघर्ष पर निर्णय

निहितार्थ: सैन्य तानाशाही ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाती है → गलत अनुमान और नए सिरे से संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है।

b. बांगलादेश - दोस्ताना से अमित्र तक?

बांगलादेश में अंतरिम सरकार से पता चलता है:

- भारत के प्रति कूटनीतिक ठंडक
- पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का कदम
- 50 साल बाद बांगलादेश का दौरा कर रहा है पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज → इससे बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाएं एक साथ खतरा पैदा करती हैं, एक दुर्लभ और खतरनाक स्थिति।

4. "शहरी आतंक" की वापसी: एक नई आंतरिक सुरक्षा चुनौती

एक। नया आतंक मॉड्यूल - एक परेशान करने वाला बदलाव

- श्रीनगर → फरीदाबाद → दिल्ली में फैला एक आतंकी मॉड्यूल
- इसमें डॉक्टर और चिकित्सक शामिल हैं, लम्घे तत्व नहीं



- अल-फलाह विश्वविद्यालय, हरियाणा से जुड़ा हुआ है
- बाबरी मस्जिद (1992) के लिए "बदला" से प्रेरित होकर घटना के वर्षों बाद पैदा हुआ था
- जमा 3,000 किलो विस्फोटक, उन्हें रिहायशी इलाकों में छिपा दिया
- लाल किलो के पास विस्फोटक से लदी कार में विस्फोट करने में कामयाब रहा

मुख्य बदलाव:

पहले की आतंकी लहरें थीं:

- 1993 आपराधिक तत्वों द्वारा →
- 2008 → पाकिस्तान प्रायोजितलेकिन 2024-25 मॉड्यूल है:
- पूरी तरह से स्थानीय
- उच्च शिक्षित
- वैचारिक रूप से कटृपंथी
- एन्क्रिटेड संचार का उपयोग करना

यह शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच घेरेलू कटृपंथ की चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत देता है।

जन्म। आंतरिक सुरक्षा के लिए निहितार्थ

- मिथक टूटा: "जम्मू-कश्मीर में कोई भी स्थानीय आतंक में शामिल नहीं हुआ"
- पेशेवर, शैक्षणिक और धर्मार्थ नेटवर्क के माध्यम से जुटाया गया धन।
- लिंक पाकिस्तान से परे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्किये तक फैले हुए हैं।

यह आतंकी खतरों में एक गुणात्मक छलांग है।

5. भारत को क्या करना चाहिए? - सतर्कता और रणनीतिक पुनर्गणना की आवश्यकता

a. बाहरी खतरे

- भारत को पाकिस्तान के साथ संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए।
- रणनीतिक बहाव को रोकने के लिए बांग्लादेश को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना चाहिए।



- दक्षिण एशिया के साथ फिर से जुड़ें और प्रभाव बहाल करें।

ख. आंतरिक सुरक्षा

- राज्यों के बीच खुफिया समन्वय को मजबूत करना।
- विश्वविद्यालयों और पेशेवर नेटवर्क के भीतर कट्टरपंथ की निगरानी करें।
- एक्स्प्रेस चैनलों पर साइबर-निगरानी में सुधार करें।

c. "धार्मिक फासीवाद" को रोकना

लेखक चेतावनी देता है कि आंतरिक कट्टरपंथ के साथ बाहरी शत्रुता समाज का ध्वनीकरण कर सकती है। भारत की ताकत इसमें निहित है:

- अनेकवृत्तिभोग
- धार्मिक सह-अस्तित्व
- लोकतांत्रिक संस्थाएं

इन्हें सतर्कता और सामाजिक सद्व्यवहार के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।

समाप्ति

भारत आज दोहरे मोर्चे पर चुनौती का सामना कर रहा है: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक अलगाव और घरेलू स्तर पर नए सिरे से आंतरिक आतंक। पाकिस्तान में सैन्य अधिनायकवाद, बांग्लादेश में बदलते सरेखण और शिक्षित युवाओं के बीच उभरते शहरी आतंकवादी मॉड्यूल का संयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। आगे का रास्ता शाश्वत सतर्कता, स्मार्ट कूटनीति और मजबूत आंतरिक सामंजस्य है। भारत को विदेशों में रणनीतिक स्थान को फिर से हासिल करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक कट्टरपंथ देश के सभ्यतागत ताने-बाने को कमज़ोर न करे।



Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Website : - <https://nitinsirclasses.com/>**
- **Youtube : - <https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf>**
- **Instagram :- <https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==>**
- **Facebook : - <https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg>**
- **Telegram : - <https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJI>**